कुत्ते के साथ रेप

धारा 377 को हटाने की बात चली। पर भादंसं से हटी नहीं। कोर्ट ने समलैंगिकता पर रोक हटाने को कहा। सरकार के पास मामला गया। कैबिनेट ने चिंतन-मनन किया। गेंद वापस न्यायपालिका के पाले में डाल दी। इस बीच किसी ने एक पिल्ले के साथ रेप कर दिया। पुलिस ने कुत्ते के साथ रेप करने वाले को धारा 377 के तहत गिरफ़्तार कर लिया और रपट लिख ली। उस आदमी ने कहा कि दो के बीच आपसी सहमति के साथ सेक्स संबंध बनाना गैरकानूनी नहीं। पुलिस ने दो डंडे जमाते हुए कहा कि बच्चू यहां मामला दो आदमी का नहीं, आदमी और पशु का है। पशु क्रूरता अधिनियम में भी फंसते हो। उस आदमी ने कहा कि कुत्ता पालतू नहीं है, मेरी तरह आवारा है। क्या किसी ने इस मामले की शिकायत की है। क्या कुत्ते ने मेरे खिलाफ़ कुछ बयान दिया है। डंडे फटकारना बंद करो। अब पुलिस वाला निरुत्तर हो गया। वह आदमी उसे समलैंगिकता का पाठ पढ़ाने लगा। अंत में कहा कि कानूनन भी मैं कहीं नहीं फंसता। मैंने किसी कुतिया के साथ रेप नहीं किया है।

भौंकने वाले

कुत्ते को जब रोटी का टुकड़ा नहीं मिलता तो वह अपने मालिक पर ही भौंकने लगता है। यही हाल अब लालू प्रसाद का है। बीते लोकसभा चुनाव में लालू ने कांग्रेस को पहले की भांति ही बहुत ही कम सीटें देनी चाही, पर कांग्रेस ने पहले ही सर्वे करवा कर यह जान लिया था कि अब लालू का राज्य में कोई खास जनाधार (वोट बैंक) नहीं रह गया है, इसलिए उसने लालू की बात मानने से इनकार कर दिया। क्षुब्ध लालू ने मुलायम के साथ मिल कर चौथा मोर्चा बना लिया। पर इस मोर्चे को कोई सफ़लता नहीं मिली। यहां तक कि स्वयं उनके अपने गढ़ माने जाने वाले दानापुर क्षेत्र में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यह तो दो जगहों से पर्चा भर रखा था, नहीं तो लोकसभा का मुंह भी नहीं देख पाते। पासवान वाली हालत हो जाती। खैर, ससंद में आने के बाद इन्हें उम्मीद थी कि इन्हें मंत्री पद फ़िर से दिया जायेगा। पर 'सलाहकारों' की सलाह पर उन्होंने लालू को 'हड्डी का टुकड़ा' क्या, 'रोटी का टुकड़ा' भी नहीं डाला। पहले जहां लालू मैडम से जब चाहें, मिल लेते थे, पर इस बार तो मिलने का भी मौका आसानी से नहीं मिला। काफ़ी कोशिशों के बाद एक बार मुलाकात हुई, पर मैडम ने ठंडा रुख अपनाया। रेलमंत्री बन कर लालू तीसमार खां बने फिरते थे, पर उनके हटते ही रेलवे को मुनाफ़ा दिलाने का दावा बुलबुले की भांति फट पड़ा। इधर लालू ने जब देखा कि मैडम और अन्य कांग्रेसी नेता उन्हें कोई भाव नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने महंगाई का मुद्दा उठा दिया और कहा कि जनप्रतिनिधियों को विशेष सुरक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए, क्योंकि महंगाई से त्रस्त जनता उनके साथ मारपीट कर सकती है। लालू की यह बात भी हंसी में उड़ा दी गई। इधर फ़िर लालू ने महंगाई का मुद्दा जोर-शोर से उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि महंगाई से अब ग़रीब जनता ही नहीं, मध्यमवर्गीय लोग़ भी परेशान हैं। सरकार ने महंगाई कम करने का वादा किया था, पर वह महंगाई रोकने में विफल रही है। इससे जनाक्रोश भड़केगा। बात तो ठीक है, पर सरकार का समर्थन कर रहे लालू को मंत्री पद मिल जाता तो क्या वे यह बात कहते? अभी तो कांग्रेस पर भौंक रहे हैं, पर टुकड़ा मिलने पर दुम नहीं हिलाते क्या?

मार्क्सवादियों का डर

माओवादियों पर पहले जब केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाना चाहा तो वामपंथी इसके विरोध में थे। लेकिन बगैर वामपंथियों के जब मनमोहन सरकार चुन कर आई तो इसने माओवादियों पर प्रतिबंध लगा दिया। पर इससे कुछ हुआ नहीं। 'मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की।' अब तक माओवादी पश्चिम बंगाल में उतने सक्रिय नहीं थे। पर सिंगूर और नंदीग्राम में ये सक्रिय हो गये। इसके बाद लालगढ़ के जंगलों में इन्होंन अपने आप को समेट लिया और उस पूरे इलाके में किसी भी राज-प्रतिनिधि के प्रवेश पर पांबदी लगा दी। लालगढ़ में नक्सली सरकार पर भारी पड़ गये। इसलिए अब बुद्धदेव भट्टाचार्य और अन्य माकपाई नेता इस बात के लिए परेशान हैं कि सरकार माओवादियों को नेस्तनाबूद करने के लिए सेना क्यों नहीं भेजती? सरकार का कहना है कि इसके लिए सेना नहीं भेजी जायेगी। नक्सलवाद के सफ़ाये के लिए विशेष बल कोबरा आदि जो बनाये गये हैं, उसी से काम चलाया जायेगा। पर इन 'बलों' से काम चलता जाये, यह संभव नहीं लगता। एक बात यह भी साफ़ हो जाती है कि सिंगूर और नंदीग्राम कों बड़ा मुद्दा बना कर ममता दीदी ने तृणमूल को मजबूत कर लिया। पर सिर्फ़ तृणमूल की इतनी औकात नहीं होती अगर पीछे से माओवादी अथवा नक्सली न होते। वामपंथी तृणमूल को बड़ा खतरा समझ रहे हैं। तीन दशकों से भी अधिक से चला आ रहा उनका अबाध शासन खत्म होने की संभावनायें पैदा हो रही हैं। कांग्रेस और तृणमूल के गठबंधन से कुर्सी पर कहीं ममता दीदी न बैठ जायें, यह डर मार्क्सवादियों को सता रहा है। वैसे अगर ममता दीदी भी राज सिंहासन पर बैठती हैं तो उनके सामने भी लालगढ़ का 'लाल खतरा' मौजूद रहेगा।

गपशप

राजनीतिक वेश्यावृत्ति

मतदान हो चुके। इस चुनाव की खासियत रही कि भारी संख्या में मतदाता वोट डालने के लिए उमड़ पड़े। अख़बारों में ख़बर आई कि मतदान का प्रतिशत 65 से 70 तक रहा। अच्छी बात है। 'प्रजातंत्र' में लोग़ों की 'आस्था' बढ़ रही है। शासकों के लिए यह सौभाग्य की बात है। अब उम्मीदवारों और वोटरों को भी परीक्षा-फल का इंतज़ार है। ऐसे जिस भांति छात्र परीक्षा देने के बाद समझ जाते हैं कि उनका रीजल्ट कैसा आने वाला है, उसी तरह हारने वाले अभी से ही हार का गम मना रहे हैं। चौटाला से टिकट खरीदने और आशीर्वाद लेने वाले खुलेआम तो नहीं, पर अंधेरे और एकांत में जा कर उसे अच्छी तरह गरिया लेते हैं और इस तरह अपना तनाव दूर कर लेते हैं। भाजपा वालों का भी यही हाल है और न जीतने के लिए कटिबद्ध चंद कांग्रेसी उम्मीदवार भी ऐसा ही कर रहे हैं। भाजपा के कुछ उम्मीदवार तो पूर्व सरसंघ चालक के.एस.सुदर्शन के शब्दों में राजनीति को 'वेश्या' तक घोषित कर रहे हैं। उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि राजनीतिक वेश्यागमन में करोड़ों खर्च उन्होंने किसी से पूछ कर किया था, या वेश्याभोग स्वेच्छापूर्वक करना चाहा था। यहां तो लॉटरी निकलती है। शेयर बाज़ार की तरह का कारोबार है। करोड़ों डूब जाने पर भी राजनीतिक वेश्यागमन का मौका नहीं मिलता।

आज नहीं तो कल....

राजगीर में आयोजित तीन दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भाजपा से काफ़ी निराशा जताई। उन्होंने साफ़-साफ़ कहा कि भाजपा संघ द्वारा समर्थित पार्टी नहीं है। यह एक ऐसी बात कह दी संघ प्रमुख ने कि लोग़ भौचक्के रह गये। आखिर भाजपा संघ को ही अना पितृ संगठन मानती है और जनसंघ से लेकर अब तक भाजपा को संघ ने ही चलाया है। फ़िर मोहन भागवत ऐसी बातें कहते हैं तो 'गणवेश' धारण करने वाले अटल, आडवाणी, राजनाथ और अनेकानेक ऊंचे ओहदों पर बैठे संघ के संन्यासियों अथवा पूर्व संन्यासियों को कैसा लगेगा? भागवत ने कहा है कि जो भी राजनीतिक दल संघ के उद्देश्यों से मिलते-जुलते काम करेगा, उसे समर्थन दिया जायेगा। उन्होंने धीरे से कांग्रेस की तरफ़ इशारा भी किया है। पर अयोध्या में राममंदिर कैसे बनेगा जिसके बारे में आडवाणी बार-बार कहते हैं कि वह बन कर रहेगा। क्या सिर्फ़ जिन्ना-जिन्ना सुनकर भागवत जी इस कदर खीज पड़े। ग़लत बात है। संघ के सपोर्ट के बिना भाजपा क्या रह जाएगी। उसे तो आत्मघात कर लेना पड़ेगा। आज तक संघ ने अच्छे अथवा बुरे दिनों में भाजपा को सहारा और संबल प्रदान किया है। हिंदू राष्ट्र के निर्माण का सपना दिखाया है। पब्लिक जब सोती है तो उसे सपने में रोटी दिखाई पड़ती है, पर भाजपा नेताओं को स्वर्ण जड़ित और जवाहरातों से जगमगाता राममंदिर दिखाई पड़ता है। आखिर अयोध्या में राममंदिर बनाने जैसा ऐतिहासिक काम भाजपा को ही करना है और एक राममंदिर बनने से इस धर्मप्राण राष्ट्र की सभी समस्याओं का हल होना है। अतः संघ प्रमुख गुस्से में न आयें। भाजपा में अभी संभावना है। अपनी संतान को सड़क पर आवारागर्दी के लिए न छोड़ें। हां, अनुशासन का पाठ पढ़ायें और दूध-बादाम खिलायें। आज नहीं तो कल.......। यह अवश्य ध्यान में रखें कि भाजपा ही मंदिरनिर्माण का कार्य कर सकते है। बाबरी मस्जिद का ध्वंस कर आधा काम तो कर दिया है। ध्वंस के बाद ही नवनिर्माण होता है। इस सत्य को मत भूलें महाप्रभु।

क्या हुआ उनका?

आख़िर उनका क्या हुआ जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाओं के चलते भाजपा को छोड़ा था और उसे धूल चटाने का संकल्प लिया था। पहले तो संन्यासिन उमा भारती और उनके प्रेमी के रूप में प्रख्यात चिंतक गोविंदाचार्य को लें। पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया तो संघ ने भी उनके घावों पर मरहम नहीं लगाया। मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री न बनाये जाने से क्रुद्ध उमा भारती ने अटल-आडवाणी को जी भर के कोसने के बाद अपनी अलग भारतीय जनशक्ति पार्टी बना ली। पर यह पार्टी न तो यूपी में और न ही एमपी में कोई धमाल कर सकी। उमा की 'सेक्सी संन्यासिन' की छवि भी मतदाताओं को लुभा पाने में कामयाब न हो सकी, क्योंकि प्यार के नशे में उन्होंने मीडिया को गोविंदाचार्य से अपने संबंधों के बारे में सब कुछ खोल कर बता दिया। इससे उनसे इकतरफ़ा प्यार करने वालों और केसरिया बाने में लिपटे उनके बदन को मालपुआ समझने वालों को काफ़ी निराशा हुई। लगातार चुनावों में हारने के बाद मीडिया ने भी उनका हाल-चाल पूछना छोड़ दिया। मीडिया में 'हॉट' नहीं रह गईं। गोविंदाचार्य 'भज गोविंदम् भज गोविदंम्, गोविंदम् भज मूढ़मते' का जाप करते हुए अपना समय बिताने लगे। बढ़ती उम्र ने उनकी इंद्रियों को शिथिल कर दिया। उमा के लिए किसी काम के रह नहीं गये। ऐसी स्थिति में उमा को रोज़ ही 'नये-नये गुरुओं' की तलाश करनी पड़ती है।

देश में ग़रीबी से युवराज परेशान

युवराज राहुल की ग्राम यात्राओं से कांग्रेस ही नहीं, दूसरी पार्टियों के नेता भी खुश हैं। वे उनकी प्रशंसा में गीत गाने लगे हैं। युवराज को ग़रीबी से बहुत ही चिढ़ है। वे ग़रीबी के मुद्दे को उठाना चाहते हैं। कहते हैं कि चुनावों में किसी भी पार्टी ने ग़रीबी के मुद्दे को नहीं उठाया। क्या उन्हें पता है कि देश में ग़रीबों की संख्या कितनी है? बहरहाल, दलितों और भूमिहीनों के घर खाने-पीने और रातें बिताने के बारे में उन्होंने साफ़ कहा कि वे पहले से तय नहीं करते कि किसके यहां रुकना है। हां, जो भी ग़रीब उन्हें दिख जाता है, उसके घर चले जाते हैं। उन्हें यह अच्छा लगता है। क्यों अच्छा न लगे? रोज़ ही रबड़ी-मलाई का रसास्वादन करने वाले का भी जी करता है कि रेहड़ी पर बिक रहे चाट-गोलगप्पे खा ले। युवराज ने यह भी कहा कि वे जाति व्यवस्था में यकीन नहीं करते। अच्छी बात है। यकीन करें या न करें, पर चुनावों में जाति के आधार पर समीकरण बनाने ही पड़ते हैं। बस ये समीकरण कैसे बनाये जाते हैं, इसकी ट्रेनिंग ले लें। इधर युवराज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी गये। यह विश्वद्यािलय 'प्रगतिशील' है और अपने 'वामपंथी नज़रिये' के लिए मशहूर है। कहीं बाहर आने-जाने में खादी का धवल वस्त्र पहनने वाले युवराज यहां जींस और शॉर्ट शर्ट पहन कर आये। छात्राओं में इनका ऑटोग्राफ लेने की होड़ मच गई। अपनी इस स्टार वैल्यू को देख कर युवराज अत्यंत प्रसन्न हुए। किसी ने विवाह के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की तो कोई जवाब नहीं दिया, शरमा गये। छात्र-छात्राओं के बीच एक छोटा-सा भाषण दिया और हाथ हिलाते हुए सुरक्षा प्रहरियों के घेरे में चले गये।

पृष्ठ 4 का शेष

नक्सली आतंक पर सैन्य कार्रवाई का सवाल

यानी ये ग़रीबों को भीख देने के समर्थक हैं। फ़िर ये सनातनी मुद्रा में आते हुए कहते हैं कि अगर पांच सौ सरकारी अधिकारी, डॉक्टर और इंजीनियर बेईमान और भ्रष्ट हैं तो पांच हज़ार ईमानदार एवं कर्मठ भी हैं। उन्हीं के भरोसे देश चल रहा है। इसके बाद ये महाशय कहते हैं कि देश के 60-70 करोड़ लोग़ वोट डाल कर जब चाहें सत्ता बदल देते हैं। क्या मेहता साहब यह भूल गये कि देश में मतदान का प्रतिशत कितना घटता जा रहा है जो इस बात का परिचायक है कि लोगों का वर्तमान व्यवस्था से मोहभंग होता जा रहा है। यही नहीं, 77 प्रतिशत आबादी 20 रुपये रोज़ाना से भी कम आमदनी पर गुजर-बसर करने पर मजबूर है। ये लोग भला उस जनतंत्र को कैसे मजबूत बना सकते हैं जिसके गुण मेहता गा रहे हैं। मेहता यह भी कह रहे हैं कि नक्सली विकास कार्यों में बाधक हैं। आखिर कैसे? आजादी मिलने के 60 साल से ज़्यादा बीत जाने के बावजूद लाखों गांवों में अभी सड़क तक नहीं है, स्कूल और अस्पताल की बात तो छोड़ें, क्या इस पिछड़ेपन के लिए नक्सली जिम्मेदार हैं? आज तक सरकार को विकास कार्य करने से किसने रोका था? सरकारी तंत्र ने तो विकास के नाम पर सिर्फ़ लूट मचाई है। अभी भी वे ऐसा ही कर रहे हैं। स्वयं राहुल गांधी ने स्वीकार किया है कि विकास के लिए खर्च किये गये एक रुपया में जनता तक सिर्फ़ दस पैसे ही पहुंचते हैं। आखिर 90 पैसे कहां चले जाते हैं? जहां तक ईमानदार अधिकारियों की बात है, अगर वे भ्रष्टाचार की बात उठाते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है। क्या नक्सली उनकी हत्या करते हैं? अब तो नक्सलवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य झारखंड के राज्यपाल ने भी यह कहा है कि नक्सली ईमानदार अधिकारियों की हत्या नहीं करते। हां, बेईमान और भ्रष्ट लोग़ों को वे छोड़ते भी नहीं। पर उनकी शक्ति और संसाधन कम हैं, इसलिए सभी भ्रष्टाचारियों को काबू कर पाना उनके वश की भी बात नहीं है। जिस दिन ऐसा हो जायेगा तो सचमुच गृहयुद्ध छिड़ जायेगा।

मेहता को यह भी नहीं भूलना चाहिये कि नक्सली कोई आसमान से नहीं उतरे हैं। ये वही लोग़ हैं जिनका शोषण अंग्रज़ों के ज़माने में भी उतना नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। सरकारी संरक्षण प्राप्त उच्च वर्गीय लुटेरे ठेकेदार और साहूकार जंगल के उत्पादों पर अपना अधिकार जमाने लगे। वे केंदू पत्ते के ठेके लेने लगे और जम कर आदिवासियों का आर्थिक शोषण तो किया ही, महिलाओं का यौन शोषण भी किया। इन्होंने बेशकीमती चिरौंजी को नमक के भाव लेने लगे। इधर आदिवासी सूखी रोटी को भी तरसने लगे। मजबूरी में आदिवासी पेड़ की पत्तियों को उबाल कर खाने लगे। ऐसे लोग़ अपने अस्तित्व को बचाने के लिये अगर हथियार उठा लेते हैं तो इसमें क्या आश्चर्य। हां, मेहता जी चाहें तो उन इलाकों को बचाने की कोशिश करें जहां अभी तक नक्सली नहीं पहुंचे हैं। इसके लिये वे सरकार को चाहें तो ब्लू प्रिंट दें सकते हैं।

ऐसी बात नहीं कि सरकार नक्सलियों का दमन नहीं कर रही है। सरकार के पास जितनी ताकत है, उसका नक्सलियों के दमन के लिए वह भरपूर प्रयोग कर रही है। बावजूद जिन इलाकों में नक्सलियों ने अपना आधार काफ़ी मजबूत कर लिया है, वहां उसे सफ़लता नहीं मिलती। जहां तक नक्सलियों के विरुद्ध सेना के इस्तेमाल की बात मेहता कर रहे हैं, सरकार ने इस विकल्प को आजमाया नहीं है, पर इसे छोड़ा भी नहीं है। तब तक मेहता साहब स्वयं काग़ज़ी गोले-बारूद उनके खिलाफ़ छोड़ते रहें।